



## The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 26<sup>th</sup> August , 2024

### Edition: International Table of Contents

<b>Page 06</b> <b>Syllabus : प्रारंभिक तथ्य</b>	युद्धपोत आईएनएस मुंबई आज श्रीलंका की पहली यात्रा पर जाएगा
<b>Page 06</b> <b>Syllabus : GS 2 : शासन</b>	शास्त्रीय भाषा केंद्रों ने स्वायत्तता की मांग की
<b>Page 07</b> <b>Syllabus : प्रारंभिक तथ्य</b>	सोनोल्यूमिनेसेंस की थोड़ी रोशनी
<b>Page 07</b> <b>Syllabus : GS 1 : प्रारंभिक तथ्य</b>	तिब्बत में लगातार होने वाली सामूहिक बर्बादी भारत में चिंता का विषय
समाचार में जनजाति	शोम्पेन जनजाति
<b>Page 09 : संपादकीय विश्लेषण:</b> <b>Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय – कमजोर वर्ग</b>	विकलांग व्यक्तियों में निवेश
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: CITES

भारतीय नौसेना का अग्रणी युद्धपोत आईएनएस मुंबई सोमवार से कोलंबो में तीन दिनों के लिए आएगा। यह श्रीलंका का उसका पहला दौरा होगा।

- यह जहाज श्रीलंकाई डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के लिए पुर्जे पहुंचाएगा और उनके रखरखाव में सहायता करेगा।



## Warship *INS Mumbai* to make first visit to Sri Lanka today

The Indian Naval Ship (INS) *Mumbai* will arrive at the port of Colombo on Monday for a three-day visit to Sri Lanka, the Indian High Commission in Colombo has said. *INS Mumbai*, the Indian Navy's frontline warship, will be received ceremonially by the Sri Lankan Navy, the High Commission said in a press release on Saturday. "This is *INS Mumbai's* first visit to Sri Lanka and will be the eighth port call by Indian Ships this year," it said. The ship will bring essential spares for the Sri Lankan Airforce-operated Dornier maritime patrol aircraft, the pilots and flight navigators of which are being trained by the Indian Navy. Apart from this, the Indian Navy also supports the aircraft's maintenance with a technical team and spares. PTI

### **INS मुंबई:**

- आईएनएस मुंबई भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, जिसे 22 जनवरी, 2001 को कमीशन किया गया था।

- यह दिल्ली श्रेणी के विध्वंसक जहाजों का तीसरा जहाज है, जिसे मुंबई में मन्नगांव डॉक लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- आईएनएस मुंबई को 2023 में मध्य-जीवन उन्नयन से गुजरना पड़ा और यह भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में काम करना जारी रखता है।
- उन्नत हथियारों से लैस, आईएनएस मुंबई में विमान-रोधी, जहाज-रोधी और पनडुब्बी-रोधी क्षमताएँ हैं।
- इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, टॉरपीडो और पनडुब्बी-रोधी रॉकेट लॉन्चरों का संयोजन है।
- यह जहाज आधुनिक रडार और संचार प्रणालियों से भी लैस है, जो इसे नौसैनिक युद्ध में एक दुर्जेय संपत्ति बनाता है।

### UPSC Prelims PYQ : 2016

**प्रश्न:** हाल ही में खबरों में रही 'INS अस्त्रधारिणी' का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?

- उभयचर युद्ध पोत
  - परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी
  - टारपीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत
  - परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत
- उत्तर: c)**



यह समाचार भारत के तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया के शास्त्रीय भाषा केंद्रों के चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जो वित्त पोषण में देरी और परिचालन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) से स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

## Classical language centres ask for autonomy

**Sreeparna Chakrabarty**  
NEW DELHI

Special centres set up for the promotion of Telugu, Kannada, Malayalam, and Odia after they were designated classical languages are demanding autonomy in their functioning in order to better carry out their functions.

India has six classical languages – Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, and Odia. While four of the centres for classical languages function under the aegis of the Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysuru, the centre for Tamil is autonomous. For the promotion of Sanskrit, dedicated universities also receive funds directly from the Union Education Ministry.

At a meeting on March 18, the project directors of the centres for Telugu,

Kannada, Malayalam, and Odia demanded that their institutes be made autonomous. Following this, the centres were asked to submit detailed project reports, which was done in June. However, no further direction has been received from the Education Ministry as of now, sources told *The Hindu*.

Once a language is notified as a classical language, the Education Ministry provides certain benefits to promote it, including two major annual international awards for scholars of eminence in the said languages. A Centre of Excellence for Studies in the classical language is set up, and the University Grants Commission is requested to create a certain number of Chairs for the classical language at least in the Central Universities.

Replying to a question in the Lok Sabha in 2020,



The Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada in Mysuru.

the Union government had said that in the previous three years, ₹643.84 crore had been spent on the promotion of Sanskrit, while ₹29 crore was spent on the other five classical Indian languages.

The sources said the chief problem facing these four language centres was that any event or activity planned for them had to

get financial sanction from the CIIL. Most of the time, the centre has to hold the event first and then get the cost reimbursed from the CIIL, making it difficult to organise many such programmes.

This also means many positions for research scholars as well as administrative staff remain vacant in the absence of regular funds.

At the Centre of Excellence for Studies in Classical Telugu in Nellore, Andhra Pradesh, as against an approved staff requirement of 36 people, only 12 are on board.

Similarly, the Centre of Excellence for Studies in Classical Odia in Bhubaneswar has the approval for 30 senior and associate fellows and 10 administrative staff, but has been able to hire only eight.

In 2023, the Education Ministry allocated ₹1.76

crore for the Odia centre but it could spend only ₹56 lakh.

“There is no funding in the centre and the Project Director has no financial drawing power – he has to take approval from the nodal officer, the Director, CIIL, and is constrained to spend from his own pocket to conduct any programme and then get it reimbursed from CIIL. This difficulty will be solved when the centre will be autonomous,” a senior official at the Odia centre told *The Hindu*.

“I have been here for the past two years. We do not have any financial resources. Only two persons are here – myself, and a daily wage employee. There are several vacancies but none have been filled yet,” the Project Director at the Centre of Excellence for Studies in Classical Malayalam said.

### पृष्ठभूमि

- ▶ भारत में छह शास्त्रीय भाषाएँ हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।
- ▶ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया के केंद्र मैसूरु के केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के अंतर्गत कार्य करते हैं।
- ▶ तमिल केंद्र स्वायत्त है, और संस्कृत प्रचार समर्पित विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

### स्वायत्तता की माँग

- ▶ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया केंद्रों के परियोजना निदेशक कामकाज में सुधार के लिए स्वायत्तता की माँग करते हैं।
- ▶ अनुमोदन और प्रतिपूर्ति के लिए CIIL पर निर्भरता के कारण केंद्रों को देरी और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

### चुनौतियाँ

➤ अनियमित फंडिंग के कारण शोध विद्वानों और प्रशासनिक

कर्मचारियों के लिए रिक्त पद।

- उदाहरणों में शामिल हैं:
- तेलुगु केंद्र: 36 स्वीकृत कर्मचारियों के पदों में से केवल 12 भरे गए।
- ओडिया केंद्र: 40 स्वीकृत कर्मचारियों के पदों में से केवल 8 भरे गए।
- मलयालम केंद्र: केवल दो कर्मचारियों के साथ संचालित होता है।

## छह शास्त्रीय भाषाएँ

### ➤ संस्कृत

- प्राचीन भाषा, भारतीय संस्कृति की आधारशिला।
- वेद, उपनिषद और महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों सहित समृद्ध साहित्यिक विरासत।
- कई भारतीय भाषाओं का आधार और दक्षिण-पूर्व एशियाई भाषाओं को प्रभावित किया। मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित और बाद में देवनागरी लिपि में लिखा गया।

### ➤ तमिल

- सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषा, 2,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी।
- संगम साहित्य सहित व्यापक साहित्यिक परंपरा। तमिलनाडु और पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा, श्रीलंका में भी बोली जाती है।
- आधुनिक तमिल संस्कृति, धर्म और कला को प्रभावित करती है।

### ➤ तेलुगु

- मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है।
- द्रविड़ परिवार से उत्पन्न, साहित्य 11 वीं शताब्दी का है।
- समृद्ध काव्य और संगीत परंपरा, संस्कृत से प्रभावित। लिपि ब्राह्मी से विकसित हुई; अत्यधिक कलात्मक।

### ➤ कन्नड़

- कर्नाटक की भाषा, जिसकी जड़ें प्राचीन हैं।
- सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाएँ 9 वीं शताब्दी की हैं, जिनमें कविराजमार्ग भी शामिल है।
- साहित्य में समृद्ध, जिसमें कई जैन, वीरशैव और आधुनिक योगदान हैं।
- कन्नड़ लिपि में लिखी गई, जो ब्राह्मी से विकसित हुई।

### ➤ मलयालम

- केरल में बोली जाती है, जिसका इतिहास 1,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्राचीन तमिल से विकसित, 12 वीं शताब्दी से अलग साहित्य के साथ।
- कविता, नाटक और गद्य में समृद्ध परंपरा। ग्रंथ लिपि से ली गई मलयालम लिपि का उपयोग करता है।

### ➤ ओडिया

- मुख्य रूप से ओडिशा में बोली जाती है।
- साहित्यिक इतिहास सरला दास की महाभारत के साथ 1,000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।

o भक्ति और लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा। कलिंग लिपि

से ली गई ओडिया लिपि में लिखी गई।

► **शास्त्रीय भाषा की स्थिति में शामिल किए जाने के लाभ:**

- o वित्तीय सहायता: भाषा के संरक्षण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए समर्पित निधियों तक पहुँच।
- o शैक्षणिक मान्यता: विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक कुर्सियों और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।
- o छात्रवृत्ति के अवसर: भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों और विद्वानों के लिए छात्रवृत्ति और पुरस्कार का प्रावधान।
- o सांस्कृतिक संरक्षण: साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को दस्तावेजित और संरक्षित करने के लिए बढ़ाए गए प्रयास।
- o वैश्विक मान्यता: भाषा की समृद्ध विरासत के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और सम्मान में वृद्धि।

**UPSC Prelims PYQ : 2015**

**प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? (2015)**

- (a) ओडिया
- (b) कोंकणी
- (c) भोजपुरी
- (d) असमिया

**उत्तर: a)**

हाल के अध्ययनों ने सोनोल्यूमिनेसेंस की यांत्रिकी के बारे में गहन जानकारी प्रदान की है, विशेष रूप से उन स्थितियों के बारे में जिनमें तरल पदार्थों में ढहते बुलबुलों से प्रकाश उत्सर्जित होता है।

## WHAT IS IT?

# Sonoluminescence: a little light

Arkatapa Basu

The human eye is adept at picking out the smallest glimmer of light in shadowed spaces and the faintest star in the heavens (but light pollution has made this very hard). Mysterious flashes of light have always piqued our interest — and this is perhaps where sonoluminescence was born.

When two German engineers were studying sonar — the use of sound to navigate, like bats — in 1934, they stumbled upon a strange phenomenon: when a small bubble trapped in a liquid is hit by powerful sound waves, it seems to produce a flash of light.

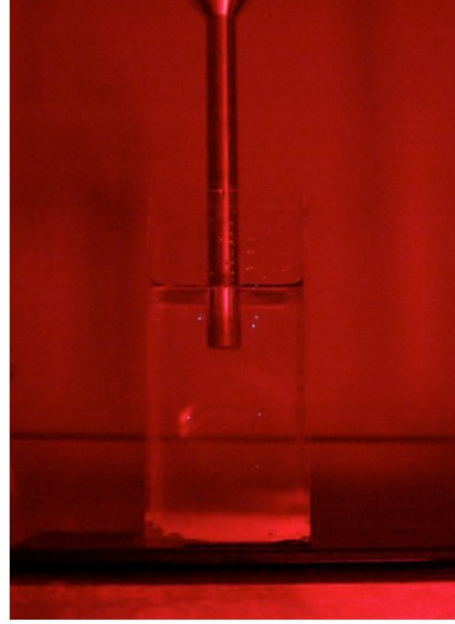
The cause turned out to be straightforward, if also fascinating: the alternating high- and low-pressure phases of sound waves caused the bubble to expand and collapse rapidly. During the collapse, the bubble compressed so intensely that the temperature inside soared to several thousand kelvin.

The extreme temperature caused gases within the bubble to ionise and release light energy in about a trillionth of a second.

We do not know how exactly this light is produced — yet.

The world has more mysteries than we like to admit.

Sonoluminescence is not restricted to labs. Pistol shrimp (family *Alpheidae*) possess a specialised claw that it can snap shut with incredible speed. The result is a jet of water moving so fast that it creates a low-pressure bubble in



Long-exposure photograph of sonoluminescence. Each bright blue point is a bubble undergoing sonoluminescence. BRIAN POLLACK (CC BY-SA 3.0)

the water. And when this bubble collapses, it generates a loud sound, intense heat, and, if you're lucky (or unlucky?) to be nearby, a fleeting flash of light.



**For feedback and suggestions** for 'Science', please write to [science@thehindu.co.in](mailto:science@thehindu.co.in) with the subject 'Daily page'

सोनोलुमिनेसेंस क्या है?

- सोनोलुमिनेसेंस एक ऐसी घटना है जिसमें तरल पदार्थ में छोटे गैस बुलबुले तीव्र ध्वनि तरंगों के संपर्क में आने पर प्रकाश के छोटे-छोटे विस्फोट उत्सर्जित करते हैं।
- जब बुलबुला तेजी से संपीड़न और विस्तार से गुजरता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है।
- ऐसा ध्वनि तरंगों के उच्च और निम्न दबाव चरणों के कारण होता है, जिससे अंदर की गैस गर्म हो जाती है और प्रकाश उत्सर्जित करती है।
- इस घटना की खोज 1934 में दो जर्मन इंजीनियरों ने की थी, जब वे सोनार तकनीक का अध्ययन कर रहे थे, जो पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है।
- उन्होंने देखा कि जब तरल पदार्थ में एक छोटे बुलबुले पर तेज ध्वनि तरंगों से प्रहार किया जाता है, तो उसमें से प्रकाश की एक छोटी सी चमक निकलती है।

### सोनोलुमिनेसेंस के पीछे का रहस्य

- हालांकि सामान्य तंत्र को समझा जा चुका है, लेकिन प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, इसका सटीक विवरण अभी भी रहस्य बना हुआ है।
- वैज्ञानिक अभी भी उन सटीक प्रक्रियाओं की खोज कर रहे हैं, जिनके कारण बुलबुले के अंदर की गैसें आयनित होती हैं और इतने उच्च तापमान पर प्रकाश उत्सर्जित करती हैं।

### सोनोलुमिनेसेंस के उदाहरण

- नियंत्रित प्रयोग: प्रयोगशाला सेटिंग में, वैज्ञानिक तरल में एक बुलबुले को फंसाकर और उसे उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों के अधीन करके सोनोलुमिनेसेंस बनाते हैं।
- पिस्तौल झींगा: जब झींगा (विशेष पंजे वाला समुद्री जीव) अपने पंजे को बंद करता है, तो वह पानी की एक धार छोड़ता है जो इतनी तेजी से चलती है कि कम दबाव वाला बुलबुला बन जाता है। फिर बुलबुला ढह जाता है, जिससे तेज आवाज़, तीव्र गर्मी और कभी-कभी प्रकाश की एक छोटी सी चमक पैदा होती है।



- सेडोंगपु गली में लगातार हो रही सामूहिक बर्बादी और तेजी से बढ़ते तापमान पर एक हालिया अध्ययन ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिंता पैदा कर दी है।

## Frequent mass wasting in Tibet a cause for worry in India

According to a new study, more than 700 million cubic metres of debris have been mobilised in the Sedongpu gully catchment since 2017; the combination of long-term warming and intense local shaking due to earthquakes has greatly enhanced landslide activity in the area

Rahul Karmakar  
GUWAHATI

**A** new study on the high frequency of mass wasting events in the Sedongpu Gully of the Tibetan Plateau since 2017 and the rapid warming of the area, which rarely experienced temperatures beyond 0°C before 2012, could be bad signs for India, specifically the country's northeast.

A geological event, mass wasting is the gravity-influenced movement of rock and soil down a slope. A gully is a landform created by erosion from running water, mass movement or both.

The Sedongpu Gully, in the catchment of the Sedongpu glacier and its valley, is 11 km long and covers 66.8 sq. km. It drains into the Yarlung Zangbo, or the Tsangpo River, near where it takes a sharp turn – called the Great Bend – while flowing around Mt. Namcha Barwa (altitude 7,782 metres) and Mt. Gyala Peri (7,294 metres) to create a gorge 505 km long and 6,009 metres deep. This is one of the deepest gorges on the earth.

The Great Bend is close to Tibet's border with Arunachal Pradesh, where the Tsangpo flows as the Siang river. In Assam further downstream, the Siang meets the Dibang and Lohit to form the Brahmaputra, which flows as the Jamuna in Bangladesh.

The study, authored by Weile Li and six others associated with China's Chengdu University of Technology, was published on August 2 in the *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*.

According to their paper, more than 700 million cubic metres of debris have been mobilised in the Sedongpu gully catchment since 2017. The combination of long-term warming and intense local shaking due to earthquakes has greatly enhanced landslide activity in the area. The impact on humans has been low because it is so remote.

However, environment scientists in Assam said the study underlining landslides was ominous for areas hundreds of kilometres downstream. The threat has been accentuated by big dams such as the 510-MW Zangmu on the Tsangpo and India's planned projects on the Siang.

### River choking and flash floods

"China plans to set up a 60-gigawatt project on the Tsangpo, which will [have] thrice the capacity of the Three Gorges project on the Yangtze, the world's largest hydropower plant," said Partha Jyoti Das, the head of the Water, Climate, and Hazard Division of Aaranyak, a Guwahati-based biodiversity research organisation. "This region is characterised by enormous geophysical instability and experienced the



The Sedongpu Gully in Tibetan China, visible just to the left of the Yarlung Tsangpo river at the centre of this image taken on December 30, 2020. GOOGLE EARTH

8.6-magnitude Assam-Tibet or Medog earthquake in 1950, one of the biggest of the 20th century. The 6.4-magnitude Nyingchi earthquake hit the same region in November 2017."

"The Sedongpu study has serious implications for the Tsangpo-Siang-Brahmaputra-Jamuna, especially in India and Bangladesh. The most direct consequence could be the addition of major amounts of sediments to the course of the river, already one of the most sediment-laden rivers of the world," he said.

The Brahmaputra carries more than 800 tonnes of sediment at Pandu in Guwahati, becoming more than a billion tonnes at Bahadurabad in Bangladesh. Dr. Das said increasing sedimentation may make the river more intensely braided in the Assam plains, which could lead to more bank erosion.

"The sedimentation can elevate the river beds more, accentuating flood hazards. Further, the channels of the river in Assam and Bangladesh may get choked with sand and silt in the lean season making navigation difficult and affecting livelihoods related to fishing," he said.

The Sedongpu study examined the patterns of landslides in the gully catchment using satellite data from December 1969 to June 2023. From 149 satellite images, they identified 19 large mass-wasting events or event groups they divided into three sub-patterns: ice-moraine avalanche (IMA), and glacier debris flow (GDF). A moraine is a mass of rocks and sediment deposited by a glacier.



The breaching of the blockages leads to catastrophic flash floods in the downstream areas such as the ones in Arunachal Pradesh's East Siang and Assam's Dhemajai district in 2000

**PARTHA JYOTI DAS**  
Head of Water, Climate & Hazard Division, Aaranyak

(IMA), and glacier debris flow (GDF). A moraine is a mass of rocks and sediment deposited by a glacier.

The debris from the IRAs temporarily blocked the Tsangpo and tributary Yigong. "The breaching of the blockages leads to catastrophic flash floods in the downstream areas such as the ones in Arunachal Pradesh's East Siang and Assam's Dhemajai district in 2000. These floods were triggered by the outburst of a dam created on the Yigong by the glaciated debris and rock materials generated during a huge landslide," Dr. Das said.

### Lull before hyperactivity

The Sedongpu study noted that the earliest mass wasting event in the area occurred from 1974 to 1975 and satellite images thereafter indicated no catastrophic events until 1987. Two IMAs happened from 1998 to 2000 and the gully remained quiet again from 2001 to 2017.

"The gully entered a very active period [in] 2017 with a large IRA from October 20-27 temporarily blocking the Yarlung Tsangpo," the paper said, underlining the Nyingchi earthquake – its epicentre was 8 km from the gully's edge – that disrupted the stability of the rocks and glaciers.

Three successive GDFs followed from November to December 2017 and two catastrophic IRAs occurred "unexpectedly" in 2018 to completely block the Tsangpo and form another gully more than 300 metres deep. "After these events, the Sedongpu gully entered an intense erosion period... Overall, among the 19 events, 13 were concentrated after 2017, accounting for 68.4% of the total," the paper said.

The geoscientists said the bedrock of the Sedongpu basin consists mostly of Proterozoic marble and the conditions indicate its land surface temperature ranges from -5° to 15° C, rarely exceeding 0° C before 2012. Data from the nearby weather stations at Bomi and Linzhi revealed that the annual temperature in this area increased at rates of 0.34° to 0.36° C during 1981-2018, which is higher than the global average. "It is high time we undertook similar studies to monitor the status and trends of geophysical events leading to landslides, rockfalls, and other erosional processes that could affect the geomorphic and hydrological regime of the Brahmaputra and its tributaries apart from attending to sediment management," Dr. Das said.

### THE GIST

➤ A geological event, mass wasting is the gravity-influenced movement of rock and soil down a slope

➤ A gully is a landform created by erosion from running water, mass movement or both

➤ Geoscientists examined the patterns of landslides in the Sedongpu gully catchment using satellite data from December 1969 to June 2023

➤ From 149 satellite images, they identified 19 large mass-wasting events or event groups they divided into three sub-patterns

### WHAT IS IT?

सेडोंगपु गली के बारे में:

- सेडोंगपु गली (29°47'7.20"N, 94°55'24"E) दक्षिण-पूर्वी तिब्बती पठार में स्थित यारलुंग त्संगपो नदी के बड़े मोड़ क्षेत्र में है।

- 1950 के दशक से दो समीपवर्ती घाटियों, अर्थात् सेडोंगपु गली (SDP)

और ज़ेलोंगनॉन्ग गली (ZLN) में मलबा बहता रहा है।

### मास वेस्टिंग घटनाओं की आवृत्ति

- 2017 से, सेडोंगपु गली जलग्रहण क्षेत्र में 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक मलबा जमा हो चुका है, जिसमें कुल 19 पहचाने गए मास-वेस्टिंग घटनाओं में से 68% से अधिक इस अवधि में हुई हैं।
- इन घटनाओं में आइस-रॉक हिमस्खलन (IRAs), आइस-मोराइन हिमस्खलन (IMAs) और ग्लेशियर मलबे का प्रवाह (GDFs) शामिल हैं।
- भूवैज्ञानिक कारण: बड़े पैमाने पर बर्बादी की बढ़ती आवृत्ति को दीर्घकालिक वार्मिंग और भूकंपीय गतिविधि के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
  - 2012 से पहले इस क्षेत्र में शायद ही कभी 0° C से ऊपर का तापमान अनुभव किया गया हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण वार्मिंग हुई है, जिससे पर्माफ्रॉस्ट अस्थिर हो गया है और भूस्खलन गतिविधि बढ़ गई है।
  - नवंबर 2017 में 6.4-तीव्रता वाले निंगची भूकंप ने भी ढलानों की अस्थिरता में योगदान दिया।

### नदी प्रबंधन के लिए चीन की योजनाएँ और निहितार्थ

- जलविद्युत परियोजनाएँ: चीन त्सांगपो नदी पर एक विशाल 60-गीगावाट जलविद्युत परियोजना का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जो नीचे की ओर तलछट के मुद्दों को बढ़ा सकता है।
  - इस परियोजना की क्षमता श्री गॉर्ज डैम की क्षमता से तीन गुना अधिक होने की उम्मीद है, जिससे भारत और बांग्लादेश में नदी प्रबंधन और बाढ़ के जोखिमों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- नदी चोकिंग और फ्लैश फ्लड: अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि बड़े पैमाने पर बर्बादी की घटनाओं से बड़े हुए तलछट से नदी के चैनल बंद हो सकते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
- ऐतिहासिक बाढ़ की घटनाएँ: अरुणाचल प्रदेश में 2000 में आई बाढ़ जैसी पिछली घटनाएँ, जो त्सांगपो नदी के मार्ग में भूस्खलन के कारण आई थीं, दिखाती हैं कि निचले इलाकों के लिए भूस्खलन कितना खतरनाक हो सकता है।
  - सेडोंगपु घाटी में चल रही भूगर्भीय अस्थिरता के कारण अब ऐसी आपदाओं की संभावना अधिक है।

### आगे की राह:

- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता: भारत को चीन के साथ कूटनीतिक प्रयासों को तेज करना चाहिए, त्सांगपो नदी पर जलविद्युत परियोजनाओं में साझा जल प्रबंधन रणनीतियों और पारदर्शिता की वकालत करनी चाहिए।
- वास्तविक समय निगरानी: भूस्खलन, अवसादन और जल प्रवाह को ट्रैक करने के लिए उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और ग्राउंड-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए उन्नत वास्तविक समय निगरानी प्रणाली स्थापित करें।

## UPSC Mains PYQ : 2021

**प्रश्न: विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख करें तथा स्थानीय मौसम की स्थिति पर उनके प्रभाव को उदाहरण सहित समझाएँ?**

**Tribe In News : Shompen Tribe**

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में कहा कि प्राचीन निकोबार द्वीप समूह में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास से किसी भी शोम्पेन को परेशान या विस्थापित नहीं किया जाएगा।



**शोम्पेन जनजाति के बारे में:**

- ▶ वे पृथ्वी पर सबसे अलग-थलग जनजातियों में से एक हैं।
- ▶ वे भारत में सबसे कम अध्ययन किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) में से एक हैं।
- ▶ वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। द्वीप का लगभग 95% हिस्सा वर्षावन से ढका हुआ है।
- ▶ शोम्पेन निवास स्थान भी एक महत्वपूर्ण जैविक हॉटस्पॉट है, और यहाँ दो राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अर्थात् कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलाथिया नेशनल पार्क और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व।
- ▶ जनसंख्या: हालाँकि जनगणना (2011) के अनुसार, शोम्पेन की अनुमानित जनसंख्या 229 है, लेकिन शोम्पेन की सही जनसंख्या आज तक अज्ञात है।
- ▶ उनमें से अधिकांश जंगल में रहते हैं और बाहरी लोगों के साथ उनका बहुत कम या कोई संपर्क नहीं होता है।
- ▶ वे अर्ध-खानाबदोश शिकारी-संग्राहक हैं और उनकी आजीविका के मुख्य स्रोत शिकार करना, इकट्ठा करना, मछली पकड़ना और थोड़े बहुत बागवानी गतिविधियाँ हैं।
- ▶ वे छोटे-छोटे समूहों में रहते हैं, जिनके क्षेत्रों की पहचान वर्षावनों को पार करने वाली नदियों से होती है।
- ▶ खानाबदोश होने के कारण, वे आम तौर पर जंगल में शिविर लगाते हैं, जहाँ वे कुछ सप्ताह या महीने रहते हैं, फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं।
- ▶ वे कई तरह के वन पौधे इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनका मुख्य भोजन पेंडनस फल है, जिसे वे लारोप कहते हैं।
- ▶ शोम्पेन अपनी खुद की भाषा बोलते हैं, जिसमें कई बोलियाँ हैं। एक समूह के सदस्य दूसरे की बोली नहीं समझते हैं।
- ▶ वे छोटे से मध्यम कद के होते हैं, उनका सिर गोल या लगभग चौड़ा होता है, नाक पतली होती है, चेहरा चौड़ा होता है और वे हल्के भूरे से पीले भूरे रंग की त्वचा और तिरछी आँखों जैसी मंगोल जैसी विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं।
- ▶ शोम्पेन में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर एकल परिवार होते हैं।
- ▶ शोम्पेन परिवार का नियंत्रण सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पास होता है, जो महिलाओं और बच्चों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- ▶ एक विवाह सामान्य नियम है, हालाँकि बहुविवाह की भी अनुमति है।

**UPSC Prelims PYQ : 2019**

**प्रश्न:** भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PVTG 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं।
2. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या PVTG की स्थिति निर्धारित करने के मानदंडों में से एक है।
3. देश में अब तक आधिकारिक तौर पर 95 PVTG अधिसूचित हैं।
4. इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ PVTG की सूची में शामिल हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) 2, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 4
- (d) 1, 3 और 4

**उत्तर: c)**



# Investing in persons with disabilities

A recent Hindi movie, *Srikanth*, starring Rajkumar Rao, narrates the story of the industrialist Srikanth Bolla and his journey of overcoming the challenge of visual impairment. In the film, the people of Srikanth's father's village ask the family not to invest in the son's education or life in general. Many parents of children with some form of disability are similarly made to believe that their offspring are not worthy of investment. Persons with disabilities (PwDs) face social stigma, marginalisation in all sectors, and discrimination in education and employment; most importantly, they struggle for dignity. Educational institutions lack the necessary infrastructure and support mechanisms and workplaces lack robust diversity policies that would give proper representation to PwDs.

## Status of education and jobs

The 2023 report by Nifty 50 constituent companies reveals that only five out of the 50 companies have more than 1% of PwDs on their rolls, with four of them being public sector companies. Similarly, data from the National Centre for Promotion of Employment for Disabled People reveals that less than 1% of India's educational institutions are disabled-friendly, less than 40% of school buildings have ramps, and approximately 17% have accessible restrooms. A report of the Sarthak Educational Trust titled 'Accessibility and Inclusion in Higher Education in India' states that reservation is provided under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, in government jobs, and incentives in non-government jobs, but there is a clear lack of implementation. The lack of infrastructure combined with the lack of inclusive policies hinders the full participation of PwDs in society. Thus, it is imperative that both public and private institutions invest in the uplift of PwDs.

The Indian education system



**Rajesh Ranjan**

lawyer-researcher who writes on public law, rights, and public engagement of Constitution

Educational institutions lack the necessary infrastructure and workplaces lack robust diversity policies to give proper representation to persons with disabilities

needs an inclusive framework to promote PwDs. For instance, Harvard University in the U.S. has Local Disability Coordinators who are specialised in helping PwDs find accommodation in the city. Similarly, Stanford University in the U.S. has a robust institutional structure which includes providing support in housing and devices to PwDs. It also has a comprehensive resource centre that supports students with disabilities. Few Indian universities provide such impressive models. In 2023, Shiv Nadar University enumerated a disability support policy, which includes providing personalised support to students on a case-by-case basis, depending on the student's health condition every semester. Based on the nature and severity of the disability, the Dean of Academics decides measures for academic accommodation and the Dean of Students for other aspects.

However, these measures are not institutionalised. Hence, they are not uniform, leaving a vast number of students from diverse backgrounds outside the walls of the university. Despite the University Grants Commission's draft accessibility and inclusivity guidelines for higher education institutions to ensure that admission announcements and advertisements are circulated in accessible formats, the presence of PwDs is not very encouraging.

In terms of employment, despite the legislative mandate of providing reservation for PwDs, and of drafting an equal opportunity policy detailing the measures proposed by the establishment to ensure an inclusive work environment and prohibit discrimination at the workplace, employers have failed to do these. For the effective implementation of these rules, States should come forward and develop a compliance mechanism. For instance, a model from Brazil can be emulated, where companies with more than 100 employees must have PwDs

comprise 2%-5% of the total workforce. In cases of non-compliance, the company may be subject to fines based on criteria such as its size and the number of times offences were repeated. Some countries have also developed incentive mechanisms. Japan, for instance, has developed a system of subsidiaries for employees who have some form of disability.

## Striving for dignity

The British artist, David Hevey, once remarked that "the history of the portrayal of disabled people is the history of oppressive and negative representation. This has meant that disabled people have been presented as socially flawed able-bodied people, not as disabled people with their own identities". The identity of PwDs is eroded in several ways. PwDs are considered by many as pitiful or helpless. Many believe that PwDs can only be in relationships with one another. Disability in addition to belonging to a "lower" caste or a particular gender creates a double/triple burden on people.

Sociologist Colin Barnes has argued that PwDs are "portrayed as objects of pity, violence, curiosity and ridicule, as burdens on society, sexually abnormal, and overall, as people incapable of community participation". This portrayal forms the basis of the societal attitude towards PwDs. Recently, three former cricketers mocked PwDs in a video that went viral after India won the World Championship of Legends. Everyday struggles and the stigmatisation and mockery of PwDs reveals the inability of so-called "able-bodied people" to treat them equally with dignity.

Abhishek Anicca in his book, *The Grammar of My Body*, writes, "My friends say disabled people can be negative. I agree. We are so negative that sometimes the able-bodied mind never reaches us. That distance is too far... It is thus those who are creating the distance [who] should bridge the gap."

**GS Paper 02 : सामाजिक न्याय – कमज़ोर वर्ग**

**(UPSC CSE (M) GS-2 : 2017)** क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में लक्षित लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? चर्चा करें। (150 w/10m)

**UPSC Mains Practice Question** भारत में विकलांग व्यक्तियों (PwD) के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। समाज में उनके समावेश और सम्मान को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (250 w /15 m)

**संदर्भ:**

- लेख भारत में विकलांग व्यक्तियों (PwD) द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक कलंक, हाशिए पर होने और बुनियादी ढांचे की कमी पर प्रकाश डालता है, खासकर शिक्षा और रोजगार में।
- समावेशिता के लिए कानूनी अनिवार्यताओं के बावजूद, खराब कार्यान्वयन और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बने हुए हैं, जो दिव्यांगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

**परिचय:**

- फिल्म श्रीकांत एक उद्योगपति की दृष्टि दोष पर काबू पाने की यात्रा पर प्रकाश डालती है और विकलांग लोगों (PwD) के प्रति सामाजिक कलंक को संबोधित करती है।
- PwD को सामाजिक हाशिए पर होने, शिक्षा में बुनियादी ढांचे की कमी और कार्यस्थलों में अपर्याप्त नीतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे अवसरों और सम्मान तक उनकी पहुँच में बाधा आती है।

**शिक्षा और रोजगार चुनौतियाँ:**

- 2023 की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल पाँच निफ्टी 50 कंपनियों के पास अपने कार्यबल में 1% से अधिक दिव्यांग हैं, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं।
- दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के डेटा से पता चलता है कि दिव्यांगों के लिए 1% से भी कम शैक्षणिक संस्थान सुलभ हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को अनिवार्य बनाता है और गैर-सरकारी नौकरियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, फिर भी कार्यान्वयन में कमी है।
- दुर्गम बुनियादी ढाँचा और सीमित समावेश नीतियाँ समाज में दिव्यांगों की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती हैं।

**शिक्षा में समावेशिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मॉडल:**

- यू.एस. में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में समावेशी ढाँचे हैं, जो विकलांग छात्रों के लिए आवास और विकलांगता सहायता प्रदान करते हैं।
- भारत में, शिव नादर विश्वविद्यालय जैसे कुछ विश्वविद्यालयों ने विकलांग छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हुए समान मॉडल लागू करना शुरू किया है।
- हालाँकि, ये उपाय संस्थागत नहीं हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली में असंगत कार्यान्वयन होता है।

### कार्यस्थल समावेशिता और नीति विफलताएँ:

- कार्यस्थल समावेशिता के लिए कानूनी अनिवार्यता के बावजूद, नियोक्ताओं ने दिव्यांगों के लिए आरक्षण या विविधता नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।
- राज्यों को इन अनिवार्यताओं के लिए अनुपालन तंत्र विकसित करना चाहिए। ब्राज़ील के एक मॉडल में अनिवार्य किया गया है कि 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के कार्यबल में 2%-5% दिव्यांग होने चाहिए, गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ।
- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए जापान की सहायक प्रणाली समावेशन को प्रोत्साहित करने का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करती है।

### सम्मान और प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष:

- ब्रिटिश कलाकार डेविड हेवी और समाजशास्त्री कॉलिन बार्न्स ने मीडिया और समाज में दिव्यांगों के नकारात्मक चित्रण की आलोचना की है।
- दिव्यांगों को अक्सर दया की वस्तु, पूर्ण सामुदायिक भागीदारी में असमर्थ या समाज पर बोझ के रूप में देखा जाता है, जो निरंतर भेदभाव में योगदान देता है।
- हाल की घटनाएँ, जैसे कि पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा उनका मजाक उड़ाना, दिव्यांगों के निरंतर कलंक को उजागर करता है।

### सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता:

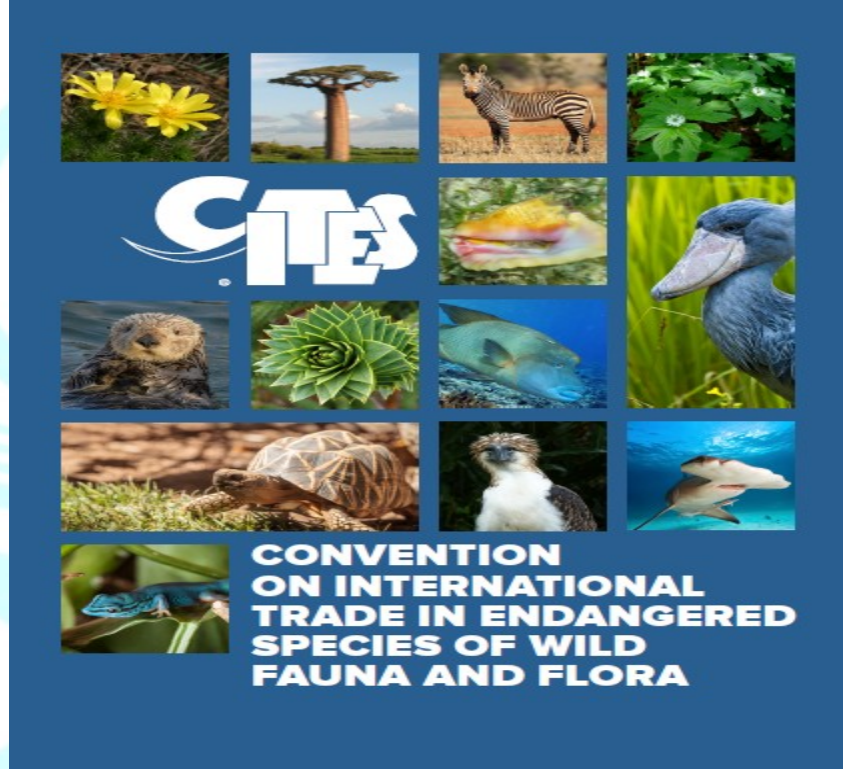
- दिव्यांगों के लिए सम्मान, प्रतिनिधित्व और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता दोनों की आवश्यकता है, जहाँ वे पनप सकें।

### दिव्यांगजनों की पहचान का क्षरण

- नकारात्मक प्रतिनिधित्व: समाज में दिव्यांगों का चित्रण अक्सर उन्हें दया या उपहास की वस्तु बना देता है। यह नकारात्मक प्रतिनिधित्व एक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जो उनकी गरिमा और पहचान को कमज़ोर करता है।
- बोझ के रूप में धारणा: समाजशास्त्रियों का तर्क है कि दिव्यांगों को अक्सर समाज पर बोझ के रूप में देखा जाता है, जो उनकी आत्म-पहचान और सामाजिक भागीदारी को प्रभावित करता है। मीडिया और सार्वजनिक प्रवचन के माध्यम से इस धारणा को पुष्ट किया जाता है।
- विकलांगता की अंतर्संबंधता: दिव्यांग जो हाशिए पर पड़ी जातियों या लिंगों से संबंधित हैं, उन्हें जटिल भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उन पर दोहरा या तिहरा बोझ पड़ता है जो उनकी पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा को और कम करता है।
- सामाजिक बहिष्कार: विकलांगता से जुड़ा कलंक अक्सर सामाजिक गतिविधियों और रिश्तों से बहिष्कार की ओर ले जाता है, जिससे यह विचार पुष्ट होता है कि दिव्यांग केवल एक-दूसरे से ही जुड़ सकते हैं, जो उनकी व्यापक सामाजिक पहचान को कम करता है।

## CITES

- ➔ पूर्ण रूप: वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन
- ➔ यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले।
- ➔ CITES को 1973 में अपनाया गया था और 1975 में लागू हुआ।
- ➔ इसमें 184 सदस्य दल हैं, और 38,000 से अधिक प्रजातियों में व्यापार विनियमित है।
- ➔ हालांकि CITES कानूनी रूप से पार्टियों पर बाध्यकारी है - दूसरे शब्दों में, उन्हें कन्वेंशन को लागू करना होगा - यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है।
- ➔ CITES सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रशासित है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- ➔ CITES राष्ट्रों के प्रतिनिधि प्रगति की समीक्षा करने और संरक्षित प्रजातियों की सूचियों को समायोजित करने के लिए पार्टियों के सम्मेलन (या COP) में हर दो से तीन साल में मिलते हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों की सुरक्षा के साथ तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
  - ➔ **परिशिष्ट I:**
    - इसमें विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियाँ शामिल हैं और वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध सहित सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
  - ➔ **परिशिष्ट II:**





○ इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो वर्तमान में विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं, लेकिन व्यापार नियंत्रण के बिना विलुप्त हो सकती हैं।

○ यदि निर्यातक देश इस निष्कर्ष के आधार पर परमिट जारी करता है कि नमूने कानूनी रूप से प्राप्त किए गए थे और व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व या पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका के लिए हानिकारक नहीं होगा, तो विनियमित व्यापार की अनुमति है।

➔ **परिशिष्ट III:**

○ इसमें ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जिनके लिए किसी देश ने अन्य CITES दलों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए कहा है।

○ परिशिष्ट III प्रजातियों में व्यापार को CITES निर्यात परमिट (परिशिष्ट III में प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाले देश द्वारा जारी) और उत्पत्ति के प्रमाण पत्र (अन्य सभी देशों द्वारा जारी) का उपयोग करके विनियमित किया जाता है।

○ देश किसी भी समय परिशिष्ट III में उन प्रजातियों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनके लिए उनके घरेलू नियम हैं।

○ CITES वन्यजीव प्राधिकरणों, राष्ट्रीय उद्यानों, सीमा शुल्क और पुलिस एजेंसियों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हाथियों और गैंडों जैसे जानवरों पर लक्षित वन्यजीव अपराध से निपटने के प्रयासों पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाता है।